चुनावी साल में बिहार को केंद्र ने दी 10 हजार करोड़ की दो और बड़ी परियोजनाएं

पटना-आरा-सासाराम फोरलेन व कोसी-मेची नदी जोड़ो को स्वीकृति

6,282 करोड़ रुपये की कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना को दी मंजूरी, बाढ़ की समस्या से मिलेगी राहत, आसपास के क्षेत्र में बढ़ेगा सिंचाई का दायरा

3,712 करोड़ के 120 किमी लंबे पटना-आरा-सासाराम फोरलेन कारिडोर को भी दी मंजूरी, यह पांच राष्ट्रीय राजमार्गों व चार राज्य राजमार्गों को जोड़ेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बिहार को लेकर दो और बड़े एलान किए हैं। इसमें 6,282 करोड़ से अधिक की कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे न सिर्फ सीमांत बिहार और कोसी के आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिलेगी, बल्कि दो लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी। इसके साथ ही 3,712 करोड़ के 120 किमी लंबे पटना-आरा-सासाराम फोर लेन कारिडोर को भी हरी झंडी दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में ये निर्णय लिए गए। कैबिनेट से जुड़े निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना का लाभ मुख्य रूप से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को मिलेगा। प्रत्येक मानसून सीजन में कोसी के 2,050 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को सिंचाई के लिए महानंदा बेसिन में मोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर को विस्तार देते हुए मेची नदी से जोड़ा जाएगा, जहां से जलधारा को महानंदा बेसिन में लाया जाएगा। परियोजना में बिहार को 3,652.56 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

पटना-आरा-सासाराम फोरलेन से पटना व बिहटा एयरपोर्ट पहुंचने में होगी सुविधा, दानापुर व पटना स्टेशन जाने में होगी आसानी

पीएम नरेन्द्र मोदी ● फाइल फोटो/एएनआइ >>

बिहार के चौतरफा विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे जहां एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं किसान भाई-बहनों की आय भी बढ़ेगी। **-नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

बिहटा-औरंगाबाद नई रेल लाइन की डीपीआर बनाने को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बिहटा-औरंगाबाद के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है। रेल लाइन की लंबाई 120 किमी होगी। राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में वैष्णव ने कहा कि डीपीआर में परियोजना के अंतिम स्थान का निर्धारण भी किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि औरंगाबाद को रेल संपर्कता प्रदान करने के लिए अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किमी नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। यह बिहटा-औरंगाबाद के बीच प्रस्तावित रेल लाइन का हिस्सा है। नई रेल लाइन के निर्माण पर 440 करोड़ के खर्च का अनुमान है। इस राशि की भी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस परियोजना के लिए 42.7 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

रेललाइन परियोजना को मिले गति

औरंगाबाद ही नहीं, बल्कि पटना, अरवल और जहानाबाद क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण औरंगाबाद-बिहटा रेल परियोजना के लिए चार दशकों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस परियोजना से करीब 90 लाख की आबादी को लाभ होगा। पहली बार 1980 में आरा से सांसद रहे चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। प्रस्ताव को स्वीकृति तो मिली, पर परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी। इसके लिए आंदोलन चलता ... परियोजना का शिलान्यास किया था। सर्वे के लिए रुपये उपलब्ध कराए, परंतु कार्य शुरू नहीं हो सका। केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार आई तो 2024 के बजट में इस परियोजना के लिए राशि उपलब्ध कराई गई। इससे आशा जगी है, लोगों की मांग है कि इसे

दैनिक जागरण इस मामले को लगातार उठाता रहा है। गत लोकसभा चुनाव में जागरण ने आमजन की इस मांग को घोषणापत्र में शामिल किया था।

इसके साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मोड (एनएएम) पर 120 किमी लंबे चार लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम सड़क कारिडोर को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,712 करोड़ होगी। मौजूदा समय में सासाराम, आरा व पटना के बीच आवागमन मौजूदा राज्य राजमार्गों (एसएच-2, एसएच-12, एसएच-81 और एसएच-102) पर निर्भर है, जबकि आरा शहर पहुंचने के लिए भारी यातायात के कारण तीन से चार घंटे लगते हैं। ग्रीनफील्ड कारिडोर के साथ-साथ मौजूदा ब्राउनफील्ड राजमार्ग के 10.6 किमी हिस्से को विकसित किया जाएगा। इससे आरा, ग्राहिणी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसे स्थानों पर घनी आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। यह परियोजना एनएच-19, एनएच-319, एनएच-922, एनएच-131जी व एनएच -120 सहित प्रमुख परिवहन गलियारों को एकीकृत करती है, जिससे औरंगाबाद, कैमूर और पटना आवागमन की सुविधा मिलेगी। परियोजना दो हवाई अड्डों (पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित बिहटा हवाई अड्डा), चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों (सासाराम, आरा, दानापुर, पटना) और अंतर्देशीय जल टर्मिनल (पटना) को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तथा पटना रिंग रोड तक सीधी पहुंच बढ़ाएगी।